Permission to Consolidated Seafood Corporation, U.S.A.

1789. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government have granted permission to a UN firm named Consolidated Seafood Corporation, USA for a Rs. 598 crore deep sea fishing project;

(b) the details of this proposals; and

(c) whether there is any Indian collaborator in the said project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : (a) to (c) Government have given permission to M/s Indfish Ltd., New Delhi to undertake deep sea fishing project in collaboration with M/s. Consolidated Sea Food Corporation, USA. The equity participation in the project between Indian and U.S. Company would be 60 : 40 respectively. The Joint Venture Company would acquire 12 Multi Liners, 48 Mini Liners and 2 Tenders (Service Vessels) for operation in Indian Exclusive Economic Zone and beyond to exploit Tuna and Tuna like resources etc. The project envisages annual catch of 40,000 Metric Tons of fish to earn foreign exchange of Rs. 546 crores.

Applications cleared under charter fishing policy, 1989

1790. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state the status of the applications made by technocrats and small entrepreneurs for chartering under the 1989 scheme of charter fishing ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : Under the 1989 charter policy announced by the Government a total number of 175 applications were received for grant of letter of intent for chartering foreign fishing vessels. No letter of intent/charter permit has been granted to any of these applicants as the 1989 charter policy has not been operationalised.

सब्जियों के उत्तम उपयोग की योजना

1791. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सब्जियों की बर्बादी को रोकने के लिए उनका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने हेतु क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) ऐसी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना-कितना लक्ष्य रखा गया और इन वर्षों में वर्षवार क्या उपलब्धि रही ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) यद्यपि राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं फिर भी इस मंत्रालय ने फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विकास के लिए सरकारी सेक्टर, संयुक्त सेक्टर, सहकारी सेक्टर यूनिटों आदि को सहायता देने हेतु आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के उद्देश्य से विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों और वर्ष 1992-93 में प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

योजना स्कीम का नाम	वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित निधि (करोड़ रुपयों में)
1	2
1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्कीम ।	1,50

1	2
2. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों और राज्य सहकारिताओं/संयुक्त क्षेत्र को सहायता देने के लिए स्कीम ।	3.00
3. प्रसंस्करणकर्त्ताओं और उत्पादकों के बीच पिछड़े सम्पर्क मजबूत करने के लिए स्कीम ।	0.75
4. खुम्बी की खेती व प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सहायता स्कीम ।	1.00
5. हॉप्स के विकास व प्रसंस्करण के लिए स्कीम	0.40
6. प्रसंस्कृत खाद्यों पर और विपणन सहायता की व्यवस्था के लिए व्यापक विज्ञापन हेतु स्कीम	1.50
7. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास	0.10
कुल :	8.25

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने भी फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए अनेक स्कीमें तैयार की हैं । यद्यपि इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं परन्तु ऐसा अनुमान है कि फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की संस्थापित क्षमता सातवीं योजना के अन्त में 9.5 लाख टन से बढ़कर आठवीं योजना अवधि के अन्त में 20 लाख टन हो जायेगी ।

Promotion of Electropathy/Electro-Homoeopathy system of medicines in India

1792. SHRI JAGANNATH SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the development and promotion of Electropathy/Electro-homoeopathy System of medicine in India;

(b) if so, what is the present stage of development;

(c) whether Government constituted an Inquiry Committee for the recognition of this system;

(d) if so, when the report of this Committee was received by the Government;

(e) whether Government appointed an Expert Committee for the recognition of Electropathy/Electro-homeopathy Medical Science; and

(f) if so, when this Committee was formed and by when the report of this Expert Committee will be submitted ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) and (b) Reports have been received of institutions and practitioners claiming to provide education and treatment based on Electropathy/Electro-homoeopathy system of Medicine. The system has, however, not been recognized.

(c) and (d) Yes, Sir. The Inquiry Committee submitted its report on 20-12-1990.

(e) and (f) Yes, Sir. The Committee constitutes on 16-5-1991, submitted its report on 4-11-1991.

Infectious diseases—Thriving under the Corpet

1793. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appeared in the Economic Times dated the 16th January, 1993 under the caption "Infections Diseases—Thriving under the Corpet";